www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 ऐतिहासिक निर्णय है जातिगत जनगणना

3 आज जानकी नवमी पर मैथिल समाज करेगा विविध...

4 तार चोरी करने के मामले में सीआईए-1 पुलिस...

वर्ष: 9 | अंक: 191 | दिल्ली, मंगलवार, 6 मई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

अब अग्निवीरों को भी शहीद होने पर मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रह राशि

चंडीगढ़ (एजेन्सी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि तथा हरियाणा के वीरता/विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार युद्ध में शहीद हुए डिफेंस तथा पैरामिलिटरी फोर्सिज सैनिकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करती है तथा अब अग्निवीरों को भी यह लाभ देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने चार वर्ष की अवधि के लिए तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) में अग्निवीर (अधिकारी रैंक कैडर से नीचे) के रूप में पुरुष और महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना के तहत, चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के अग्निवीर के रूप में नामांकित किया जाता है। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। अब तक पिछले दो वित्तीय वर्षों, 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा के सभी जिलों से कुल 5120 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। इसके अलावा 2024-25 के दौरान, हरियाणा से लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती हुई है।

प्रियंका ने कलपेट्टा में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया

वायनाड (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कलपेट्टा में नये पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया और वहां इसके संचालन की समीक्षा की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ कार्यालय पहुंची कांग्रेस महासचिव का क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (कोझिकोड) अरुण मोहन और अन्य लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान सांसद ने केंद्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या 120 तक बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया। प्रियंका गांधी ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान नया पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि यह लोगों के लिए खुला है क्योंकि यह उनके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। यह एक मोबाइल प्रणाली भी है जो अधिक दूरदराज के इलाकों में जाती है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र में प्रतिदिन लगभग 40 पासपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और उन्हें यकीन है कि यह संख्या बढ़ेगी।

गुरदासपुर में पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक

गुरदासपुर (एजेन्सी)। सीमा सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण उल्लंघन में, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 3-4 मई की मध्य रात्रि में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया, जब उसे पंजाब के गुरदासपुर जिले में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया। घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के निवासी मोहम्मद अजमल के बेटे हुसैन के रूप में हुई है। उसे सीमा सुरक्षा बाड़ के आगे फल्कू नाला के पास भारतीय क्षेत्र में करीब 250 मीटर अंदर सीमा स्तंभ संख्या 63/एम के संरेखण में पकड़ा गया। यह स्थान बीएसएफ के साहपुर अग्रिम सीमा चौकी के निगरानी क्षेत्र में आता है, जो बीओपी दरिया मंसूर से सटा हुआ है। यह घटना 3 मई को रात करीब 11:10 बजे हुई, जब पीटीजेड कंट्रोल रूम में एचआईटी प्वाइंट नंबर 01 पर तैनात सीटी संदीप घोष ने इलाके में संदिग्ध हरकत देखी। उन्होंने तुरंत कंपनी कमांडर को सूचित किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर 'जी' के साथ एक त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) मौके पर पहुंचा। टीम ने इलाके की घेराबंदी की और रात 11:45 बजे तक संदिग्ध को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।

7 मई को हो एक मॉक ड्रिल: गृह मंत्रालय

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जिनके बॉर्डर पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे हुए हैं। उन्हें एक तरह से निर्देश दिया गया है कि 7 मई को एक मॉक ड्रिल करें। इस प्रकार का मार्क ड्रिल कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो आपको सिविल डिफेंस सिस्टम के तहत वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो फॉलो करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, इस मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड सायरन बजाने, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना (इवैक्यूएशन प्लान) जैसी गतिविधियां शामिल रहेंगी।

इन कदमों से साफ लग रहा है कि भारत की सरकार आतंकवाद को लेकर जीरो टालरेंस के मूड में नजर आ रही है। जिस प्रकार का बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। इसी क्रम में भारत के एक्शन के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुस्साहस होता है तो उसे उसके अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। फिलहाल भारत की लड़ाई आतंकवाद को लेकर है। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद जिस तरह का रिएक्शन देगा उससे ज्यादा और जोरदार जवाब दिया जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे राज्यों के लोग उसी प्रकार से तैयार रहें।

मॉक ड्रिल में किन बातों पर फोकस

- अगर एयर स्ट्राइक होता है तो उसका सायरन किस प्रकार से बजाया जाना चाहिए। जिससे लोगों को पहले ही सूचना मिल जाए।
- हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस पर नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या क्या करना है। अगर किसी को चोट लगी
- क्रैश ब्लैक आउट उपायों का प्रावधान
- अगर कोई बड़े प्लांट हैं, तो उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए।
- निकासी योजना का अद्यतनीकरण और उसका पूर्वाभ्यास

दिल्ली महिला आयोग को जल्द ही दोबारा सक्रिय किया जाएगा: रेखा गुप्ता

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ समय से निष्क्रिय दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) को जल्द ही फिर से सक्रिय किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने यह बात राष्ट्रीय महिला आपके घर जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कही। राष्ट्रीय महिला आपके घर जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि संकट में फंसी महिलाएं सहायता के लिए सरकार की ओर देखती हैं और वर्तमान में लगभग 1,500 ऐसे मामले लंबित हैं। रेखा ने कहा, इसीलिए दिल्ली महिला आयोग को पुनः सक्रिय किया जाएगा और यह आयोग फिर से कार्य करना शुरू करेगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने आवास पर हाल में हुई एक जन सुनवाई का उल्लेख किया, जिसमें एक अभिभावक ने शिकायत की थी कि कुछ लड़के उनकी बेटियों को लगातार परेशान कर रहे हैं, जबकि इस संबंध में पहले ही एक शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है। रेखा ने कहा, ऐसे लोग गलती करते रहेंगे, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने घोषणा की कि शहर के चिन्हित अंधेरे वाले स्थलों पर 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंधेरे वाले स्थान केवल वे नहीं हैं जहां रोशनी कम है, बल्कि वे क्षेत्र भी हैं जहां नेटवर्क संपर्क कमजोर है।

'वन दिल्ली, वन नंबर': परवेश वर्मा का बड़ा ऐलान

अब दिल्लीवासियों के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 311, सभी विभाग होंगे एक कमांड सेंटर से जुड़े

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। मानसून से पहले दिल्ली सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में अब NDMC, MCD, DDA, PWD, जल बोर्ड और फ्लड विभाग से जुड़ी सभी नागरिक सेवाओं की शिकायतें एक ही नंबर 311 पर दर्ज की जा सकेंगी। इस एकीकृत हेल्पलाइन नंबर की घोषणा आज PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने NDMC के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद की।

मंत्री ने कहा, वन दिल्ली, वन नंबर- यही हमारा लक्ष्य है। अब लोगों को यह सोचने की जरूरत नहीं कि समस्या किस विभाग की है। नागरिक केवल 311 पर कॉल करें और उनकी शिकायत संबंधित विभाग तक तुरंत पहुंचा दी जाएगी। यह नई व्यवस्था खासतौर से मानसून सीजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जलभराव, टूटी सड़कें, बंद नाले या ओवरफ्लो सीवर जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को अब किसी विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे।

PWD मंत्री ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर सभी संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कमांड सेंटर की संचालन प्रणाली, विभागों के प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति, जवाबदेही तंत्र और तकनीकी एकीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

श्री वर्मा ने बताया कि ऐसे सभी स्थान, जो मानसून के दौरान जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं और जहाँ अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे। इससे समस्या की पहचान रियल-टाइम में हो सकेगी और संबंधित विभाग तुरंत मौके पर कार्रवाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा, जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान मौके पर तुरंत हो, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है। CCTV कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग के जरिए हमारी टीमें तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेंगी।

311 हेल्पलाइन और साझा कमांड सेंटर के माध्यम से दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के मॉडल को मजबूत कर रही है। यह पहल मानसून के दौरान दिल्लीवासियों को राहत देने के साथ-साथ भविष्य की स्मार्ट सिटी अवधारणा की दिशा में भी अहम कदम साबित होगी।

नदी जल पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक और हम किसी के साथ पानी साझा नहीं करेंगे: सीएम

पंजाब के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया-भगवंत मान

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि पंजाब नदी जल के बंटवारे के बारे में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के किसी भी फैसले को नहीं मानेगा।

जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.बी.एम.बी. का गठन वास्तव में सतलुज और ब्यास के पानी के प्रबंधन के लिए हुआ था। ये दोनों नदियाँ पंजाब में बहती हैं जिसके कारण इन पानी पर पूरी तरह पंजाब का हक है। हरियाणा या राजस्थान का इन नदियों से कोई लेना-देना नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बी.बी.एम.बी. के जरिए कई सालों से पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार ने इस बोर्ड को अपने राजनीतिक हितों के लिए

इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब से पूछे बिना आधी रात को बैठकें बुलाकर और दूसरे राज्यों के दबाव में आकर पंजाब का हक छीना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और बी.बी.एम.बी. के माध्यम से पंजाब के अधिकारों पर डाका मारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी ढंग से बी.बी.एम.बी. की बैठक बुलाकर पंजाब का पानी जबरदस्ती हरियाणा को देने की कोशिश की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हरियाणा 31 मार्च तक अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भाजपा सरकार चाहती है कि पंजाब के हक का पानी हरियाणा को दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में भगवंत मान सरकार ने पंजाब के हर खेत को नहर का पानी पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि नहरों और खालों का नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर कायम किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि साल 2021 तक पंजाब के सिर्फ 22 फीसदी खेतों तक नहर का पानी पहुंचता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब के लगभग 60 फीसदी खेतों तक नहर का पानी पहुंच रहा है, इसीलिए अब पंजाब के पानी की एक-एक बूंद पंजाब के लिए बहुत कीमती हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास अब अपने हिस्से का पानी किसी और राज्य को देने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली 6 अप्रैल को हरियाणा ने पंजाब से अनुरोध किया था कि उसे पीने के लिए पानी की जरूरत है।

भगवंत सिंह मान ने पंजाब ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने हिस्से में से हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी दे दिया; क्योंकि हमारे महान गुरु साहिबान ने हमें सिखाया है कि किसी भी प्यासे को पानी देना बहुत बड़े पुण्य का काम है।

पानी पर पंजाब ओछी राजनीति न करें: सीएम नायब सिंह सैनी

'पानी एक प्राकृतिक स्त्रोत और देश की धरोहर है'

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी के मुद्दे पर पंजाब ओछी राजनीति कर रहा है। इससे पहले भी एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दर किनार किया। पानी प्राकृतिक स्त्रोत है और यह देश की धरोहर है। आज भी हरियाणा के हिस्से का पीने का पानी न देने पर मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जो अनैतिक है और भारतीय संघीय ढांचे के खिलाफ है।

मुख्यमंत्री हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव सिख समाज के दसो गुरूओं द्वारा दिखाए मार्ग के खिलाफ है। मान सरकार को गुरूओं के वचन को निभाना चाहिए और बिना शर्त पानी छोडना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व आप पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बाबा साहिब के पवित्र सविधान का सम्मान करे। सविधान की पुस्तक गांव गांव लेकर घूमते है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की हरियाणा मंत्रिमंडल ने घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि 1966 से पहले पंजाब व हरियाणा एक ही था। मान साहब इस प्रकार की छोटी राजनीति छोडकर विकास की राजनीति को अपनाए और पंजाब के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो भी राजनीतिक दल रहे है पंजाब के लोगों ने एक-एक को जवाब दिया है।

मुख्यमंत्री ने मान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को लाइन में खडा कर दिया उसी प्रकार आप को भी खडा कर देंगे। पंजाब विधानसभा में बीबीएमबी को भंग करने के सम्बंध में पारित किए गए प्रस्ताव पर पुछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी लोकसभा से पारित एक स्वायत निकाय है और केंद्र सरकार के अधीन है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार न तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानता, न सविधान को मानता और भारतीर संघीय ढांचे की अवेहलना करता है। एक सिस्टम है उस पर देश चलता है। उन्होंने पंजाब के नेताओ से आग्रह किया है कि गुरूओं ने जो रास्ता दिखाया उस पर मान सरकार को चलना चाहिए।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी, सूचना, जनसम्पर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. एम पांडुरंग, मीडिया सचिव श्री प्रवीण अत्रे भी उपस्थित रहे।

सीएजी की कार्रवाई रिपोर्टों की निगरानी हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगी दिल्ली विधानसभा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लेखा परीक्षा अनुपालन और वित्तीय सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान श्री गुप्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों पर त्वरित रूप से कार्रवाई की गई टिप्पणियां प्रस्तुत करने के महत्व को दोहराया तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री अजय माहावर भी उपस्थित थे।

बैठक में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम और सीएजी की रिपोर्ट टिप्पणियों की समीक्षा के विषयों पर चर्चा की गई। इस पहल का उद्देश्य उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा लेखा परीक्षात्मक निष्कर्षों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। बैठक में श्रीमती रोली शुक्ला मालगे, महालेखा परीक्षक (ऑडिट), आशीष चंद वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव

(वित्त), डॉ. एस.बी. दीपक, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सन्नी कुमार सिंह, आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलास कर विभाग, दानिश अशरफ, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विजेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एस.एस. परिहार, विशेष सचिव, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विचार-विमर्श के दौरान अध्यक्ष ने सभी विभागों से अनुरोध किया कि वे सीएजी की अनुशंसाओं का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें तथा ATNs समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने वित्तीय अनुशासन और संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया। सभी विभागों ने लेखा परीक्षा की समीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया।

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की पहल के अंतर्गत, सीएजी रिपोर्टों पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ATNs की निगरानी हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त प्रणाली के मॉडल पर आधारित होगा तथा इसे दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जा रहा है।

इस पोर्टल को 23 जून 2025 तक विधिवत रूप से शुरू करने का लक्ष्य है। इससे संबंधित तकनीकी परीक्षण, कस्टमाइजेशन तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रक्रिया में है। पोर्टल के माध्यम से ATNs को ऑनलाइन प्रस्तुत, सत्यापित और संसदीय समितियों द्वारा संसाधित किया जा सकेगा। साथ ही सभी संबंधित पक्ष वास्तविक समय में इसकी निगरानी कर सकेंगे, जिससे लेखा अनुपालन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

रिजर्व बैंक ने 2024-25 की दूसरी छमाही में 25 टन सोना बढ़ाया

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तवर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में अपने भंडार में लगभग 25 टन सोना बढ़ाया है। इस अवधि में सोने की कीमतों में वृद्धि देखी गई थी। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। केंद्रीय बैंक के पास अब अपने भंडार में 879.59 टन सोना है, जबकि सितंबर 2024 के अंत में उसके पास 854.73 टन सोना था। वित्तवर्ष 2024-25 में, केंद्रीय बैंक ने अपने भंडार में सोने की मात्रा 57 टन और बढ़ायी, जिस अवधि के दौरान सोने की कीमतों में 30 प्रतिशत की तेजी देखी गई थी। यह पिछले सात वर्षों में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय रूप से संग्रहीत कीमती धातु की मात्रा मामूली रूप से बढ़कर 511.99 टन हो गई। स्थानीय तिजोरियों में रखे सोने के अलावा, 348.62 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) के पास था और 18.98 टन सोना जमा के रूप में रखा गया था।

दिल्ली के तैमूर नगर में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को किया जा रहा ध्वस्त

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। यहां 100 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है।

एक्शन से इलाके में के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफएस, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीम भी मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को तैमूर नगर नाले के आसपास अतिक्रमणों को ध्वस्त करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शुक्रवार को बारिश और आंधी के बाद दक्षिण दिल्ली सहित राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ के लिए अतिक्रमण के कारण नाले में बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाने को जिम्मेदार ठहराया।

अधिकारियों को 28 अप्रैल को न्यायालय के निर्देशानुसार सोमवार को नाले के आसपास अतिक्रमणों को ध्वस्त करना है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा 14 निवासियों द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि वे तैमूर नगर एक्सटेंशन में इंदिरा गांधी कैंप पार्ट-1 में झुग्गियों में रहते हैं, जिसे ध्वस्तीकरण के लिए निर्धारित स्थल के अंतर्गत बताया गया है।

निवासियों ने दावा किया कि वे 1985 से इस स्थल पर रह रहे हैं और उन्हें 26 अप्रैल को ध्वस्तीकरण के संबंध में नोटिस मिला, जिसके अनुसार उन्हें अपना परिसर खाली करना होगा।

सम्पादकीय

कबाड़ से जुगाड़

कबाड़ से जुगाड़ सिर्फ. एक तरीका नहीं, बल्कि एक रचनात्मक दर्शन है जो संसाधनशीलता और नवाचार को बढ़ावा देता है। यह अपसाइकल की गई रचनाओं और सरल समाधानों के माध्यम से अपरंपरागत सोच की शक्ति का प्रमाण है। कबाड़ से जुगाड़ का दर्शन बेकार वस्तुओं को उपयोगी बनाने और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर जोर देता है। यह दर्शन हमें नए और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, जो मौजूदा समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं और इससे कचरे को कम करने और पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। यह आत्मनिर्भरता का भी दर्शन है, जो हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह दर्शन जटिल समस्याओं के लिए सरल और व्यावहारिक समाधान खोजने पर जोर देता है। जुगाड़ एक बोलचाल का हिंदी शब्द है जिसका मतलब है अपरंपरागत, किफायती नवाचार। कबाड़ से बने म्यूरल, पार्क और अन्य कलाकृतियां कबाड़ से जुगाड़ के उपक्रम को दर्शाती हैं। कबाड़ से बनाए गए टेलीस्कोप, लेजर लाइट ब्लोइंग कार, वाटर प्यूरीफायर आदि कबाड़ से जुगाड़ के उदाहरण है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जुन्नारदेव जनपद पंचायत के बरेली पार गांव के ग्रामीणों का कबाड से बना स्वच्छता पार्क एवं मेरठ का कबाड़ से जुगाड़ अभियान ऐसे विरल एवं अनुकरणीय उदाहरण हैं जो राष्ट्रीय फलक पर चमक रहे हैं। कबाड़ से जुगाड़ बेकार की वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाने की एक प्रक्रिया है। कबाड़ से जुगाड़ ना केवल हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत सहायक है बल्कि यह अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान का भी एक सटीक उपाय है। इसके माध्यम से हम ऐसी अनुपयोगी वस्तुओं को फेंकने की जगह उनसे कुछ उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया जा सकता है, जो. रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता की दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। हम भारतवासी वैसे भी जुगाडू होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। यदि हम अपनी रचनात्मकता कबाड़ से जुगाड़ में लगाएं तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे कचरे के निपटान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे प्लास्टिक एवं ई-कचरे में निरंतर कमी आती जाएगी और पर्यावरण संरक्षण भी बढ़ेगा। संसाधनों पर वह भी बोझ कम पड़ेगा। मेरठ का कबाड़ से जुगाड़ अभियान अब राष्ट्रीय फलक तक चमका, एक सकारात्मक सोच एवं सृजन का अनूठा उदाहरण बन गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के 93वें संस्करण में योगी आदित्यनाथ सरकार के इस प्रयास की काफी सराहना की। शहरों को संवारने के प्रदेश सरकार के सपनों को साकार करते हुए मेरठ नगर निगम ने निष्प्रयोज्य वस्तुओं से कम लागत में ही शहर की आभा में चार चांद लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह प्रयास पर्यावरण की सुरक्षा और शहर के सुंदरीकरण से जुड़ा है। निष्प्रयोज्य वस्तुएं स्क्रैप, पुराने टायर, कबाड़, खराब ड्रम से भी कम खर्चे में कैसे शहर को संवारा जा सकता है, मेरठ इसकी बानगी है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सुंदरीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी मिसाल है। खराब पड़ी चीजों का प्रयोग कर शहर को सजाया गया। गांधी आश्रम चौराहा, गढ़ रोड पर लोहे के स्क्रैप, पुराने पहियों से फाउंटेन निर्मित कराया गया। सर्किट हाउस चौराहे पर लाइट ट्री, पुराने बेकार ड्रमों से स्ट्रीट इंस्टलेशन, हाथ ठेली के बेकार पहियों से बैरिकेडिंग कर मिनी व्हील पार्क, जेसीबी के पुराने टायरों से डिस्प्ले वॉल, पार्कों में बैठने के लिए स्टूल मेज आदि की व्यवस्था की गई। मेरठ नगर निगम ने शहर को चमकाने के लिए अनोखे प्रयोग किए, जो काफी सफल रहे। दरअसल नगर निगम में बने गोदाम में पड़े कबाड़ की न तो उचित कीमत मिल रही थी और न ही इसका सही उपयोग एवं निपटान हो रहा था, पर योगी सरकार की पहल पर नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा ने शहर को जगमगाने का निर्णय लिया। लाइटिंग वाला कृत्रिम पेड़ भी न सिर्फ लोगों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। इसकी आभा देख लोग निहाल और अचंभित हो रहे हैं। कबाड़ से जुगाड़ का मतलब है बेकार पड़ी चीजों से कुछ उपयोगी या रचनात्मक बनाना, जैसे कि कचरे से सुंदर सजावटी वस्तुएं, या बेकार प्लास्टिक से जूते-चप्पल बनाना। ग्रामीणों ने कबाड़ से एक सुंदर स्वच्छता पार्क बनाया, जिसमें सजावटी वस्तुएं, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता से संबंधित कलाकृतियाँ शामिल हैं। बच्चों को सिखाने के लिए कबाड़ के सामान से खिलौने बनाए जा सकते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप, लेजर लाइट ब्लोइंग कार, रबर बैंड नाव, टेबल लैंप, वाटर प्यूरीफायर आदि। बेकार लकड़ी, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों से फर्नीचर बनाया जा सकता है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, और अलमारी। कबाड़ से कलाकृतियाँ बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पेंटिंग, मूर्तिकला, और सजावटी वस्तुएं। पुराने कपड़ों से नए कपड़े या बैग बनाए जा सकते हैं। कबाड़ से खाद और अन्य उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं, जो खेती के लिए उपयोगी हो सकती हैं। जयपुर फुट, यह एक कृत्रिम अंग है जो कम लागत में बनाया जाता है और यह जुगाड़ मानसिकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्लास्टिक के कबाड़ को रिसाइकल करके उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि प्लास्टिक दाना जो फुटवियर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। कबाड़ से विभिन्न उपकरण बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पानी फिल्टर, यांत्रिक उपकरण आदि।

जयंती

मोतीलाल नेहरू

जन्म: 6 मई, 1861- मृत्यु: 6 फरवरी, 1931) भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम 'स्वरूप रानी' था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मोतीलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपनी ज़िंदगी की शानोशौकत को पूरी तरह से ताक पर रख दिया बल्कि देश के लिए परिजनों सहित अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मोतीलाल नेहरू अपने समय में देश के प्रमुख वकीलों में थे। वह पश्चिमी रहन-सहन, वेषभूषा और विचारों से काफी प्रभावित थे। किंतु बाद में वह जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो उनके जीवन में परिर्वतन आ गया। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के शीर्ष वकीलों में थे। उस समय वह हजारों रुपए की फीस लेते थे। उनके मुवक्किलों में अधिकतर बड़े जमींदार और स्थानीय रजवाड़ों के वारिस होते थे, किंतु वह गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं रहते थे।

पुण्यतिथि

शिव कुमार बटालवी

जन्म-23 जुलाई, 1936; मृत्यु-6 मई, 1973) पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि थे, जो उन रोमांटिक कविताओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिनमें भावनाओं का उभार, करुणा, जुदाई और प्रेमी के दर्द का बखूबी चित्रण है। शिव कुमार बटालवी ऐसे शायर और कवि थे जो एक छोटी-सी जिंदगी में इतना नाम बना गये कि आज भारत में हर नौजवां के सीने में धड़कते हैं। उनके गीतों में ह्यबिरह की पीड़ाह्न इस कदर थी कि उस दौर की प्रसिद्ध कवयित्री अमृता प्रीतम ने उन्हें बिरह का सुल्तान नाम दे दिया। शिव कुमार बटालवी यानी पंजाब का वह शायर, जिसके गीत हिंदी में न आकर भी वह बहुत लोकप्रिय हो गया। उसने जो गीत अपनी गुम हुई महबूबा के लिए बतौर इश्तहार लिखा था, वो जब फि ल्मों तक पहुंचा तो मानो हर कोई उसकी महबूबा को ढूंढ़ते हुए गा रहा था-'इक कुड़ी जिहदा नाम मोहब्बत गुम है'।

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

ऐतिहासिक निर्णय है जातिगत जनगणना

वर्ष 1931 में जब देश में अंग्रेजों की सरकार थी तब जातिगत जनगणना हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें ही रहीं किंतु कांग्रेस ने कभी भी जातिगत जनगणना करवाने का साहस नहीं किया अपितु पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्बरम तक ने सदन मे खड़े होकर 16 बिन्दुओं को आधार मानकर जातिगत जनगणना का कड़ा विरोध किया था और इसे देशहित के खिलाफ बताया था

-मृत्युंजय दीक्षित

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर किये गये हिन्दू नरसंहार के बाद जनमानस में उपजे आक्रोष और पाकिस्तान पर कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा आम जनमानस तथा राजनैतिक दल उस समय हैरान रह गए जब केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा निर्णय सुनाया। केंद्र सरकार का यह निर्णय आते ही देश का राजनैतिक विमर्श जातिगत जनगणना पर केन्द्रित हो गया। आमजन यद्यपि यह सोच रहा है कि इस समय जब हम आतंकवादियों के शवों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री जी को ये क्या सूझ पड़ी, किन्तु आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है तो अवश्य इसके पीछे कुछ रणनीति होगी। उधर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन इसे अपनी विजय बताकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। कांग्रेस तो इतनी आतुर हो गई कि उसने सोशल मीडिया पर, सरकार उनकी, सिस्टम हमारा कैप्शन के साथ राहुल का प्रचार आरम्भ कर दिया, फिर उनको याद दिलाना पड़ा कि ये फिल्म में एक खलनायिका द्वारा कहे गए शब्द हैं जो आतंकवादियों के साथ है।

पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी ने कदा रुख अपनाया है और कहा है, हम आतंकवादियों तथा उनके पीछे छुपे लोगों का धरती के अंत तक पीछा करेंगे और सजा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस बार पाकिस्तान को कल्पना से अधिक दंड मिलने की बात भी कही है। संभव है, इस प्रक्रिया में समय लगे और लम्बे समय तक युद्ध की परिस्थितियां बनी रहें। उस समय में विपक्ष अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्याह्क्या कर सकता है? स्वाभाविक रूप से जाती जनगणना जैसे मुद्दों को हवा देगा। भारत की अवश्यम्भावी विजय के उपरांत विपक्ष के पास क्या मुद्दा होगा? स्वाभाविक है वो पुनः अत्यंत आक्रामक रूप से जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाएगा यही कारण है कि केंद्र सरकार ने पहले ही जातिगत जनगणना का निर्णय लेकर उन वर्गों की चिंताओं को दूर कर दिया है जो मानती है कि जातिगत जनगणना उनके पक्ष में होगी और जिनको विश्वास में लेकर राहुल गाँधी तथा उनके मित्र देश और समाज का वातावरण बिगाड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता के विचारों को आत्मसात करते हुए तथा संघ को अपने निर्णय में साथ लेकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है।

कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को एक राजनतिक हथियार के रूप में उपयोग करके 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के मिशन 400 को पूरा होने से रोक दिया यद्यपि उसके बाद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में भाजपा के नए नारों एक रहेंगे नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे ने परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल दीं। वर्तमान में भारत -पाक के मध्य चल रहे तनाव के समय सरकार द्वारा लिया गया जातिगत जनगणना का निर्णय विपक्ष के लिए तनाव पैदा करने है भले ही इस समय वो इस फैसले को अपनी जीत मानकर जश्न मना रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सहयोगियों व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर विरोधी दलों के खतरनाक राजनीतिक एजेंडे पर पॉलटिकिल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और एक बड़ा मुद्दा उनके हाथों से छीन लिया है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन और सदन के बाहर हमेशा यही कहते थे कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम संसद से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करवाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके इस कथन का पटाक्षेप कर दिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर केवल राजनीति ही करती रही है।

वर्ष 1931 में जब देश में अंग्रेजों की सरकार थी तब जातिगत जनगणना हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें ही रहीं किंतु कांग्रेस ने कभी भी जातिगत जनगणना करवाने का साहस नहीं किया अपितु पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह सरकार के गृहमंत्री पी चिदम्बरम तक ने सदन मे खड़े होकर 16 बिन्दुओं को आधार मानकर जातिगत जनगणना का कड़ा विरोध किया था और इसे देशहित के खिलाफ बताया था। यह एक कटु सत्य है किआज जिस कांग्रेस के नेता राहुल गाँधी जातिगत जनगणना के नाम पर देश को अराजकता की आग में झोकने का प्रयास कर रहे हैं उस कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया और इसे लागू नहीं होने दिया।

पत्रकार वार्ता में जातिगत जनगणना के निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातिगत जनगणना कराना समता, समरसता, सुशासन और सामाजिक न्याय के एक नये युग का आरंभ है। अब जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है। भाजपा ने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया। स्मरणीय है कि जब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतिश कुमार इंडी गठबंधन में शामिल थे और उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तब बीजेपी ने भी उस बैठक में भाग लिया था और जातिगत जनगणना का समर्थन किया था यद्यपि बीजेपी को विपक्ष के तौर तरीकों पर आपत्ति थी क्योंकि जनगणना मूलतः केंद सरकार का विषय है और इसमें राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। अभी तक जिन राज्यों में यह जनगणना हुई है वह राजनीति से प्रेरित तथा सामाजिक तनाव बढ़ाने वाली रही है।

केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना से पहली बार वास्तविक आंकड़े सामने आयेंगे। इस जनगणना के माध्यम से कई चीजे स्पष्ट हो सकेंगी जिसमें एक यह बड़ा मुददा भी है कि हर जाति के दंबग लोग ही आरक्षण का लाभ उठाते चले आ रहे हैं जबकि उन्हीं जातियों और समाज के अन्य लोग पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, उन्हें आरक्षण व सरकार की अन्य सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है अर्थात क्रीमिलेयर का भी वास्तविक वर्गीकरण हो सकेगा।

विपक्ष की जातिगत जनगणना केवल हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करने की नीयत से थी जबकि मोदी सरकार अब संपूर्णता के आधार पर जातिगत जनगणना कराने जा रही हैं देश के इतिहास में पहली बार मुस्लिम समाज की जातियों की भी जनगणना होने जा रही है। इस जनगणना के माध्यम से धर्मांतरण करने वालों का आंकड़ा भी जुटाया जायेगा। धर्म परिवर्तन करने के कारण देश के कई हिस्सों की जनसंख्या और भौगोलिक संरचना में तेजी से बदलाव देखा गया है ।ऐसे में सरकार के यह भी पता करने का इरादा है कि किन धर्मों और जाति विशेष के लोगों में धर्मांतरण हुआ और किस हिस्से में इसका प्रभाव अधिक है। जातिगत जनगणना का परिणाम सामने आने के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा मिल सकेगा। वंचित समूहों के लिए नीतियां बनाने में मदद मिल सकेगी संसाधनों और अवसरो का समान वितरण हो सकेगा तथा सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलने के साथ जाति व्यवस्था के कारण होने वाले भेदभाव की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

जातिगत जनगणना पर संघ का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है कि यदि जातिगत जनगणना का उद्देश्य न्याय और कल्याण है तो समर्थन योग्य है और यदि उसका उद्देश्य राजनीति और समाज को बांटना है तो उसका सदैव विरोध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस निर्णय का समर्थन किया है। संघ का विचार है कि जाति का अंत आांकड़ों से नहीं, आत्मीयता से होगा लेकिन आंकड़ो के बिना न तो नीति बनेगी न्याय मिलेगा। वैसे भी संघ का मूल कार्य सामाजिक समरसता ही है और वह आगामी समय में सामाजिक समरसता का एक महा अभियान चलाने वाला है। वर्तमान जातिगत जनगणना का स्वरूप संघ के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

जातिगत जनगणना की बात सामने आने पर कई विचारक इसमें सनातनी गोत्र को भी जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि हिन्दू समाज की रचना में गोत्र, किसी भी समाज के सनातन ऋषि परम्परा से जुडाव को स्थापित करता है। हिन्दू जीवन के सभी सोलह संस्कारों तथा पूजा एवं दान के संकल्प में गोत्र का नाम लिया जाना अनिवार्य होता है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

युद्ध हुआ तो पश्चिमी और चीनी हथियारों की क्षमताओं की भी परख हो जायेगी

विश्लेषकों का यह भी अनुमान है कि ड्रोन या जमीन से लॉन्च की गई मिसाइल से हमला होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि इनमें पायलट के पकड़े जाने का खतरा नहीं होता। जहां तक दोनों देशों की मिसाइल और सैन्य ड्रोन क्षमता में ताजा वृद्धि की बात है तो आपको बता दें कि भारत ने इजराइल से लड़ाकू ड्रोन हेरोन मार्क 2 प्राप्त किया है और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है

-नीरज कुमार दुबे

भारत और पाकिस्तान के बीच मंडराते युद्ध के खतरे को लेकर कई पूर्व सैन्य अधिकारी और विशेषज्ञ अपनी अपनी तरह से चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एअर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों ने अपनी सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि की है। इसलिए विशेषज्ञों को लग रहा है कि कोई सीमित संघर्ष भी व्यापक युद्ध में तब्दील हो सकता है। हम आपको याद दिला दें कि दोनों देश 1948, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ चुके हैं। इसके अलावा कश्मीर को लेकर दोनों के बीच कई बार सैन्य और असैन्य टकराव भी हो चुके हैं। 1990 के दशक में दोनों देश परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बन गए थे और तभी से दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

पाकिस्तान लगातार भारत को परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहा है लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक अत्यधिक मजबूरी नहीं हो, तब तक कोई भी देश परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करता लेकिन इसका खतरा अवश्य बना रहता है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इस बार हमला संभवतः विमानों, मिसाइलों या ड्रोन के जरिये होगा, जिनमें भारत और पाकिस्तान की क्षमताएं काफी हद तक बराबर हैं। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यदि संघर्ष लंबा चलता है तो यह भारत के हित में होगा क्योंकि संसाधन अधिक होने के कारण वह लंबी अवधि तक इनका उपयोग कर पायेगा। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि हर पक्ष सोच रहा है कि वे पिछली बार की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं लेकिन असल जंग में ही असली स्थिति पता चल सकेगी।

हम आपको बता दें कि भारत को 2019 में पुराने रूसी विमानों पर निर्भर रहना पड़ा था। मगर अब देश ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स वायुसेना के बेड़े में शामिल किए हैं तथा नौसेना के लिए और भी विमानों का ऑर्डर दिया गया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 2022 से चीन के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक, J-10 प्राप्त किया है, जो राफेल का तुलनात्मक समकक्ष माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास कम से कम 20 J-10 विमान हैं। बताया जाता है कि ये विमान उन्नत क्षमताओं से लैस हैं। हम आपको बता दें कि राफेल में 'मेटेओर' एयर-टू-एयर मिसाइल लगी होती है, जो दृश्य सीमा से बाहर भी मार कर सकती है। इसी प्रकार J-10 में इसी तरह की PL-15 मिसाइल लगी होने की बात मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आई है। हम आपको यह भी बता दें कि 2019 की लड़ाई में सामने आई हवाई सुरक्षा की खामियों को दूर करने के लिए भारत ने रूस की S-400 मोबाइल एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली प्राप्त की है जबकि पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 प्रणाली हासिल की है जोकि रूस की S-300 प्रणाली पर आधारित है।

विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले किसी भी संघर्ष पर चीन का प्रभाव बना रहेगा, जो भारत का प्रतिद्वंद्वी और पाकिस्तान का करीबी सहयोगी और उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, भले अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने का आग्रह किया है, लेकिन वह दोनों देशों के बीच किसी भी संघर्ष को चीन की सैन्य क्षमता की जांच के रूप में देखना चाह रहा है। अमेरिका ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि चीनी विमान और उसकी PL-15 मिसाइल को अब तक युद्ध में नहीं परखा गया है। इसलिए भले युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा जायेगा मगर असल में यह पश्चिमी और चीनी तकनीक के बीच मुकाबला हो सकता है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत के लिए एक चुनौती यह भी रहेगी कि वह कितने स्क्वाड्रन पाकिस्तान सीमा पर तैनात करे और कितने चीन सीमा पर, क्योंकि उसे ड्रैगन से भी खतरा है। हम आपको याद दिला दें कि भारत और चीन ने 1962 में युद्ध लड़ा था और 2022 में दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा पर भिड़ी थीं।

विश्लेषकों का यह भी अनुमान है कि ड्रोन या जमीन से लॉन्च की गई मिसाइल से हमला होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि इनमें पायलट के पकड़े जाने का खतरा नहीं होता। जहां तक दोनों देशों की मिसाइल और सैन्य ड्रोन क्षमता में ताजा वृद्धि की बात है तो आपको बता दें कि भारत ने इजराइल से लड़ाकू ड्रोन हेरोन मार्क 2 प्राप्त किया है और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने तुर्की से बायरेक्टर TB2 और अकिंजी ड्रोन हासिल किए हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान ने शनिवार को 450 किमी की दूरी तक मारक क्षमता और सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने एक्स इंद्र अभ्यास के तहत 120 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली 'फतह' सीरीज की मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण करने का भी दावा किया है। वहीं भारत की क्षमताओं में 300 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी की अग्नि श्रृंखला की अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं।

बहरहाल, हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 की झड़प के बाद कहा था कि देश को उस समय राफेल की कमी खली थी। उन्होंने संकेत दिया था कि अगर फ्रांसीसी फाइटर होते तो नतीजा और अलग हो सकता था। इसलिए माना जा सकता है कि इस बार कमाल दिखाने का अवसर राफेल को दिया जा सकता है। कांग्रेस के नेता बार-बार राफेल पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि उस पर से नींबू मिर्ची कब हटेगी? माना जा रहा है कि राफेल की युद्धक क्षमता दिखा कर पाकिस्तान के साथ-साथ कांग्रेस को भी जवाब देने की तैयारी है। हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में राफेल खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर मोदी सरकार को घेरना चाहा था लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। बहरहाल, आइये देखते हैं दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के परिणामों के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी एसपी वैध क्या अनुमान लगा रहे हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

भारत के खौफ से 5 हजार करोड़ फूंक चुका है पाकिस्तान

(एजेन्सी)।

पाकिस्तान। पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई की संभावना और आशंका से घबराए पाकिस्तान ने भारत के साथ लगती सीमा पर अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण अपनी नौसेना को भी तैयार रखा है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 10 दिन बाद यानी 2 मई तक पाक सेना ने दहशत में ही लगभग 5 हजार करोड़ रुपए फूंक डाले। सूत्रों के अनुसार, इस खर्च में हाल में तुर्किये और चीन से खरीदे गए सैन्य साजोसामान शामिल नहीं हैं। सामान्य दिनों में पाक का रोज का सैन्य खर्च लगभग 45 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा खर्च फाइटर जेट सॉर्टी (उड़ान) और सैनिकों के मूवमेंट पर किया गया है।

पाकिस्तान ने अपने लगभग 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है। कई एयरस्ट्रिप को फिर से ऑपरेटिव बनाया गया है। साथ ही सेनाओं को एलओसी (नियंत्रण रेखा) पर मूव कराया गया है। पाकिस्तान आर्मी को भारतीय सेना की ओर से सबसे ज्यादा खतरा एलओसी के पास पीओके (पाक के कब्जे वाले कश्मीर) पर चल रहे टेरर कैंपों पर हमले का है। पाकिस्तान की आमर्मी इस थ्योरी पर चल रही है कि भारत की ओर से इन कैंपों को तबाह करने के लिए बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख के बीच रेलवे मिलिट्री ट्रेन के परिचालन के लिए तैयार है। रेलवे हर छह मिनट के अंतराल पर सैन्य साजो सामान से लदी ट्रेन चलाने में सक्षम है। आपात स्थिति में यात्री ट्रेनों की टाइमिंग को रो-शेड्यूल या रद्द करने का ब्लू प्रिंट तैयार है।

रेलवे के एक अफसर का कहना है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे ज्यादातर रेलवे रूट पर परिचालन उत्तर रेलवे करता है। उत्तर रेलवे के तहत पड़ने वाली करीब 9 जगहों से सैन्य साजो सामान और युद्ध सामग्री को लोड अनलोड कर सकते हैं।

हूतियों ने तेल अवीव एयरपोर्ट उड़ाया, भड़के नेतन्याहू ने बदले की खाई कसम

(एजेन्सी)।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरुशलम में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले के बाद दोषियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई। नेतन्याहू ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ बैठक के दौरान कहा कि पूरी दुनिया हौथियों द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिसमें आज बेन-गुरियन हवाई अड्डे के पास उनके द्वारा किया गया नृशंस हमला भी शामिल है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री ने हूतियों के साथ ईरान के संबंधों की आलोचना करते हुए कहा कि इजराइल देश को एक उचित चेतावनी देगा कि यह जारी नहीं रह सकता। क्रिस्टोडौलाइड्स राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में साइप्रस और इजराइल के सहयोग पर चर्चा करने के लिए यरुशलम में थे। इजराइल के तेल अवीव के बेन मुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को यमन से बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। कई लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। हवाई अड्डे की सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई। इजराइली सेना हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है। मिसाइल टर्मिनल 3 पार्किंग के पास सड़क पर गिरी थी। हमले के बाद भारत के नई दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली एअर इंडिया के फ्लाइट को अबू धाबी डायवर्ट कर दिया गया है। एअर इंडिया ने तेल अवीव के लिए अपनी सभी फ्लाइट मंगलवार तक सस्पेंड करने की घोषणा की है। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ अपने अभियान को बढ़ाने के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाने की घोषणा की है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट गाजा में अभियान को व्यापक बनाने के लिए तैयार है। इजराइल ने मार्च में हमास के साथ संघर्ष विराम समाप्त कर दिया था और अब हमास को अपनी शर्तों पर युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर कर रहा है।

कगिसो रबाडा की गुजरात टाइटंस में होगी वापसी, ड्रग्स को लेकर हटा बैन

(एजेन्सी)।

गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी कगिसो रबाडा पर ड्रग्स लेने के चलते बैन लगाया गया था। अब इस खिलाड़ी की टीम में वापसी हो सकती है। क्योंकि रबाडा पर लगा बैन अब हट चुका है। उन्होंने ड्रग सेवन उपचार कार्यक्रम भी पूरा कर लिया है जिसके बाद अब इस खिलाड़ी की आईपीएल टूर्नामेंट में वापसी हो सकती है।

कगिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के लिए इस आईपीएल सीजन की शुरूआत में दो मैच खेल चुके हैं। इस खिलाड़ी ने पहला मैच पंजाब किंग्स और दूसरे मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला। इसके बाद रबाडा को उनके देश साउथ अफ्रीका बुला लिया गया, क्योंकि उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का दोषी पाया गया था। खिलाड़ी के प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने की वजह उन्हें नियमों के अनुसार कुछ समय के खेल से दूर रखा गया।

कगिसो रबाडा ने भारत आने से पहले जनवरी में SA20 के दौरान डोपिंग टेस्ट कराया था। खिलाड़ी का ये डोपिंग टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया। इस कारण से साउथ अफ्रीका के डोपिंग निरोधक नियमों के मुताबिक अस्थायी समय के लिए रबाडा के क्रिकेट खेलने पर बैन

लगाया गया था। इस बात की जानकारी एक प्रेस रिलीज के जरिए सामने आई।

बारिश की भेंट चढ़ा सनराइजर्स हैदराबाद-दिल्ली कैपिटल्स मैच

(एजेन्सी)। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का 55वां मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 133 रन ही बनाए। जिसके जवाब में बारिश के कारण सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी नहीं कर पाई और मैच को रद्द घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरूआत बेहद खराब रही। टीम ने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए। करुण नायर खाता नहीं खोल पाए। फाफ डुप्लेसी ने तीन रन बनाए। वहीं अभिषेक पोरेल 10 गेंद में 8 रन ही बना पाए। ये तीनों विकेट पैट कमिंस ने झटके।

सोना 550 रुपये उछलकर 97,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर

(एजेन्सी)।

वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरार्फा बाजार में सोने की कीमत 550 रुपये बढ़कर 97,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सरार्फा संघ ने यह जानकारी दी।

99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 96,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी सोमवार को 550 रुपये बढ़कर 96,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सत्र में सोने की कीमत 96,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि, चांदी 400 रुपये टूटकर 96,700 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 97,100 रुपये प्रति किलोग्राम रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 46.34 डॉलर बढ़कर 3,286.83 डॉलर प्रति औंस हो गया। कोटक सिक्योरिटीज में एवीपी-जिंस शोध कायनात चैनवाला ने कहा, मंगलवार से शुरू होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक से पहले डॉलर में नरमी के कारण सोना 3,280 डॉलर प्रति औंस हो गया। उन्होंने कहा, ...बाजार प्रतिभागी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, जेरोम पावेल की निर्णय के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सतर्कता से नजर रख रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिकी-चीन व्यापार घटनाक्रमों को लेकर अनिश्चितता से जोखिम भावना सतर्क रहने की संभावना है। चांदी की हाजिर कीमत 1.24 प्रतिशत बढ़कर 32.41 डॉलर प्रति औंस हो गई।

सितारे जमीं पर में आमिर खान पेश करेंगे 10 नए कलाकार

(एजेन्सी)। आमिर खान ने अपनी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म तारे जमीन पर (2007) की आध्यात्मिक सीक्वल, सितारे जमीन पर का पहला पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर से पता चलता है कि आमिर इस फिल्म में बास्केटबॉल कोच की भूमिका में नजर आएंगे, जो मूल फिल्म में उनके आर्ट टीचर के किरदार से मिलता-जुलता है। फिल्म की रिलीज की तारीख भी 20 जून घोषित की गई है। इस फिल्म के जरिए 10 नए कलाकार बॉलीवुड में पदार्पण करेंगे। 2007 की सुपरहिट फिल्म तारे जमीं पर की अगली कड़ी बताई जा रही यह फिल्म 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का निर्देशन शुभ मंगल सावधान के निर्देशक आर एस प्रसन्ना ने किया है और इसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने निर्मित किया है। पोस्टर पर फिल्म की टैगलाइन है-सबका अपना अपना नॉर्मल। आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, एक फिल्म जो प्यार, हंसी और खुशी का जश्न मनाती है। फिल्म सितारे जमीं पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म में आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। उनके साथ दस नए कलाकार फिल्म में नजर आएंगे। इन नवोदित कलाकारों में आरूष दत्ता, गोपी कृष्ण वर्मा, सम्वित देसाई, वेदांत शर्मा, आयुष भंसाली, आशीष पेंडसे, ऋषि शाहानी, ऋषभ जैन, नमन मिश्रा और सिमरन मंगेशकर शामिल हैं। फिल्म की पटकथा दिव्य निधि शर्मा द्वारा लिखी गई है। इसे आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने मिलकर निर्मित किया है। फिल्म का संगीत प्रसिद्ध तिकड़ी शंकर-एहसान-लॉय ने तैयार किया है जबकि गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके गीत लिखे हैं। फिल्म सितारे जमीं पर के साथ आमिर खान की लगभग तीन वर्षों बाद सिनेमाघरों में वापसी हो रही है। उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगस्त 2022 में रिलीज हुई थी।

आज जानकी नवमी पर मैथिल समाज करेगा विविध आयोजन

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार होंगे मुख्य अतिथि

एसबी संवाददाता

वाराणसी। माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में सीता नवमी मनाई जाती है जिसे जानकी नवमी भी कहा जाता है। इस बार यह तिथि 6 मई को पड़ रहा है। इसे मैथिली दिवस के रूप में भी मनाने की परंपरा है।

यह दिन सम्पूर्ण भारत के साथ ही मिथिलावासियों के लिए विशेष है इस दिन काशीस्थ मिथिलावासी अपने अराध्य मां सीता जिन्हें जानकी और मैथिली भी कहा जाता है के प्रकाट्य उत्सव के लिए विशेष तैयारी करते हैं।

कार्यक्रम संयोजक गौतम कुमार झा एडवोकेट ने बताया कि मैथिल समाज, उत्तर प्रदेश द्वारा सीता नवमी पर विविध आयोजन रखा है सर्वप्रथम सुबह कन्याओं का विधि-विधान से पूजन किया जायेगा। श्रीराम-सीता विवाह की झांकी सजाई जायेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक डा विजय कपूर सोहर की प्रस्तुति देंगे।

इस अवसर पर मिथिला के लोकनृत्य और लोक संस्कृति की मनोहारी प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की जायेगी।

कार्यक्रम इन्द्रपुर, शिवपुर स्थित रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में रखा गया है। समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार होंगे और अध्यक्षता रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ कमलेश झा करेंगे।

विधायक राजेंद्र गुर्जर को बनाया याचिका व सदाचार समिति का सदस्य

संजना भारती संवाददाता

टोंक। देवली राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए समितियों का गठन किया गया। जिसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा की गई। स्पीकर देवनानी ने विधानसभा के नियमों के तहत सोलहवीं विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन करते हुए सभापति और सदस्यों की नियुक्ति की गई हैं।

देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर को याचिका व सदाचार समिति का सदस्य बनाया गया है। विधायक गुर्जर ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार जताते हुए कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है। उस पर पूरा खरा उतरते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों को गंभीरता के साथ उठाएंगे। वहीं इधर कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने विधायक गुर्जर को सोशल मीडिया व कॉल कर सदस्य बनाएं जानें की बधाई दी हैं।

मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन के सकारात्मक नतीजे सामने आए

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 60,000 रुपये रिश्वत मांगने वाले बीडीपीओ दफ्तर का सुपरिंटेंडेंट गिरफ्तार

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है जिसके तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज की गई शिकायत के बाद अमृतसर में एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। इस हेल्पलाइन के द्वारा विजिलेंस की कार्रवाई इस जन पहल की बढ़ती सफलता को उजागर करती है और यह मुहिम सरकारी दफ्तरों में भ्रष्ट गतिविधियों का पदार्फाश करके नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सतनाम सिंह, ब्लॉक विकास और पंचायत दफ्तर (बीडीपीओ), वेरका ब्लॉक, रानी का बाग, अमृतसर के सुपरिंटेंडेंट के रूप में हुई है, जिसने गली पर कब्जे की शिकायत पर सरकारी कार्रवाई के बदले गांव नबिपुर, जिला अमृतसर के एक निवासी से 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने बीडीपीओ ब्लॉक वेरका लखविंदर कौर को शिकायत दी थी कि उसके पड़ोसी गुरविंदर सिंह ने उसके घर जाने वाली गली पर अवैध कब्जा कर लिया है। बीडीपीओ ने यह मामला उक्त सुपरिंटेंडेंट को आगे भेज दिया, जिसने इस शिकायत पर जूनियर इंजीनियर मोहित कुमार और पंचायत सचिव अशोक कुमार को तथ्यों की पुष्टि करने के निर्देश दिए थे।

इस जांच की पुष्टि से पता चला कि सरकारी गली पर कब्जा करने की शिकायत सही थी, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति पर 3,284 रुपये का जुमार्ना लगाया गया। बार-बार नोटिस देने के बावजूद, कब्जाधारी ने इस नोटिस का पालन नहीं किया, जिसके कारण बीडीपीओ दफ्तर को गैर-कानूनी ढांचे को हटाने के लिए पुलिस सहायता की विनती करनी पड़ी।

हालांकि उचित कानूनी कार्रवाई करने की बजाय, सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह ने शिकायतकर्ता की एक और शिकायत पर कार्रवाई करने के बदले 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की और शिकायतकर्ता को 20,000 रुपये अग्रिम रूप से देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने गूगल पे के माध्यम से 10,000 रुपये उक्त सतनाम सिंह के खाते में डाल दिए। इसके बाद विभाग ने पुलिस की सहायता से गली में लगे अवैध थंबों को हटा दिया गया।

इसके उपरांत शिकायतकर्ता के पड़ोसी ने बदले की कार्रवाई करते हुए गांव का नाला ब्लॉक कर दिया था, जिससे शिकायतकर्ता को मजबूरन पुनः उक्त सुपरिंटेंडेंट के पास जाना पड़ा। सतनाम सिंह ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह पहले दी गई रिश्वत के बारे में चुप रहे, नहीं तो वह उसकी नाले के बारे में दी गई शिकायत में कोई मदद नहीं करेगा।

विजिलेंस ब्यूरो ने विजिलेंस ब्यूरो के थाने, अमृतसर रेंज में सतनाम सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज करने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि की और उसे दोषी साबित होने पर गिरफ्तार कर लिया। उसे कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले में बीडीपीओ लखविंदर कौर की भूमिका की जांच आगे की जांच के दौरान की जाएगी।

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो सहिष्णुता नीति की पुष्टि करते हुए नागरिकों से सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी या दर्व्यवहार के किसी भी मामले की सक्रियता से रिपोर्ट करने की अपील की है। विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन लोगों के लिए भ्रष्टाचार की शिकायत करने का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी नागरिकों को बिना किसी डर के आगे आने का आह्वान करते हैं क्योंकि समय पर दी गई जानकारी ही तुरंत कार्रवाई को सुनिश्चित करती है।

केंद्र में भाजपा हो या कांग्रेस, पंजाब के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ: अमन अरोड़ा

'आप' के प्रदेश प्रधान ने पंजाब के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्र सरकारों को आड़े हाथों लिया

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। दशकों से पंजाब के पानी की लूट करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और हरियाणा सरकार पर तीखा हमला करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रधान और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पंजाब के साथ पानी के मामले में हुए ऐतिहासिक अन्याय का पदार्फाश किया।

सदन को संबोधित करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि कैसे पंजाब को 1955 से योजनाबद्ध ढंग से अपने जल संसाधनों से वंचित रखा जा रहा है। इस के बाद 1960 में इंडस जल संधि से पंजाब के 80% नदी जल को पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। उन्होंने बताया कि कैसे बाद के समझौतों-जैसे कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम (1966), त्रिपक्षीय समझौता (1981), और मनमाने ढंग से पानी के मूल्यांकन-ने पंजाब को उसके आधिकारिक हिस्से से भी वंचित कर दिया। श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के साथ बार-बार धोखा किया गया है- चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की। उन्होंने हमेशा पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है, हमारा पानी और अनाज लेते रहे पर बदले में कुछ नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पंजाब के रिपेरियन राज्य होने के बावजूद इसका पानी छीनकर हरियाणा और राजस्थान जैसे गैर-रिपेरियन राज्यों को गैर-कानूनी ढंग से पानी दिया गया, जो अंतरराष्ट्रीय रिपेरियन कानूनों का उल्लंघन था। 1955 में, पंजाब का पानी मूल्यांकन 15.85 एम.ए.एफ. था, लेकिन 1981 तक, इसे फर्जी तौर पर बढ़ाकर 17.17 एम.ए.एफ. दिखा दिया गया ताकि हरियाणा और राजस्थान को और पानी दिया जा सके।

श्री अमन अरोड़ा ने शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पंजाब के स्टैंड को कमजोर करने में निभाई भूमिका की भी कड़ी निंदा की, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बादल के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 जुलाई, 1978 को एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी, भले ही पता था कि यह पंजाब के अधिकारों के विरुद्ध है। 31 मार्च, 1979 को, शिरोमणि अकाली दल सरकार ने खुशी से हरियाणा द्वारा एसवाईएल के निर्माण के लिए भेजे गए 1 करोड़ रुपये हासिल किए और पंजाब के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए। बाद में केंद्र, राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दबाव में मार्च 1981 में त्रिपक्षीय समझौते को स्वीकार कर लिया।

हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने के विरुद्ध मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दृढ़ स्टैंड की प्रशंसा करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "पंजाब के पास देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। हम दिल्ली या हरियाणा के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।" उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होने की अपील की, और कहा कि पंजाब का अस्तित्व दांव पर है।

श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब के साथ बेइंसाफी करने वाले पानी के बंटवारे वाले सभी समझौतों को रद्द करने और रिपेरियन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान को बेसिन राज्य न होने के कारण नर्मदा का पानी देने से जवाब दिया जा सकता है, तो पंजाब को अपना पानी गैर-रिपेरियन राज्यों को देने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, "पंजाब देश का पेट भरता है, पर इसके अपने बच्चे पानी को तरस रहे हैं। अब बहुत हो गया-हम इस विश्वासघात को और बर्दाश्त नहीं करेंगे।" उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे केंद्र की बोली सरकार के कानों तक पंजाब की आवाज पहुंचाने के लिए एकजुट हों।

एसडीएम बारा को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन

संजना भारती संवाददाता

बारा। सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार प्रदेश के सभी तहसीलों में जातिया जनगणना को लेकर लंबे समय से संघर्ष व मांगे चल रही थी जिसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार बिंद अपने सैकड़ो साथियों के साथ एसडीएम बारा को ज्ञापन दिया। जल्द से जल्द जाति जनगणना करने की मांग भी किया। उपस्थित रहे मंत्री प्रतिनिधि पीतांबर लाल बिन्द, प्रधान असरवई, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत, अभय राज, दिना सौरव, विधानसभा अध्यक्ष राम अनुज कुशवाहा, फाफामऊ विधानसभा अध्यक्ष विकास कुमार कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे।

पानी के रक्षक कहलवाने वालों ने कभी भी पंजाब के हकों की रक्षा नहीं की

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा में पंजाब के पानी संबंधित प्रादेशिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी प्रस्ताव पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने स्पष्ट कहा कि किसी को देने के लिए पंजाब के पास पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों की गलत नीतियों के कारण पंजाब को आज यह दिन देखना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही पानी की कमी से जूझ रहा है और राज्य के कई ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक हवाले और तथ्यों के साथ पंजाब के पानी की हुई लूट के बारे में विस्तार से बताया। सौंद ने कहा कि 80 के दशक में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकारें थीं और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष पानी के हकों के लिए खड़े होने के बजाय घुटने टेक दिए थे। उन्होंने साफ शब्दों में पानी की लूट के लिए अतीत में कांग्रेस की नीतियों को दोषी करार दिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब प्रांत बनाने के समय भी केंद्र की सरकारें, खासतौर पर कांग्रेस की सरकार ने धोखा किया और पंजाब को अपनी राजधानी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस आर एस नरूला ने भी कहा था कि चंडीगढ़ की मांग समेत पंजाबियों की सभी मांगें जायज हैं। उन्होंने कहा कि कई बार कांग्रेस का दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है और कांग्रेसी नेताओं की कहनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सौंद ने कहा कि पानी के रक्षक कहलवाने वाले लोगों ने कभी भी पंजाब के हकों की रक्षा नहीं की।

तथ्यों के साथ जानकारी देते हुए सौंद ने कहा कि 100 फीसदी पानी में से पंजाब सिर्फ 24.58 फीसदी पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि राजस्थान 50.09 फीसदी, हरियाणा 20.38 फीसदी, जम्मू-कश्मीर 3.80 फीसदी और दिल्ली 1.15 फीसदी पानी का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पूरा पानी भी पंजाब इस्तेमाल करे, तो भी राज्य के पास पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि रीपेरियन कानून के मुताबिक पानी पर पंजाब का हक बनता है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 क्यूसिक पानी का मूल्य 1.25 करोड़ रुपये बनता है। इस हिसाब से यदि पानी का मूल्य मिल जाए, तो पंजाब दुनिया का सबसे अमीर राज्य होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सोना, कोयला और तेल सहित बाकी जमीनी खनिज मुफ्त में नहीं मिलते, तो पानी क्यों मुफ्त दिया जा रहा है।

50 साल बाद मलोट की टेलों तक पहुंचा नहरी पानी

पंजाब की मान सरकार ने किसानों के सपने किए सच-डॉ. बलजीत कौर

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। बी.बी.एम.बी द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़ने के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि पंजाब के पानी अधिकार और किसानों के हक के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि भारत की आजादी के बाद पंजाब के साथ हमेशा पानी बंटवारे में बेइंसाफी हुई है। नाजायज संधियों और कानूनों के माध्यम से पंजाब के अधिकारों की लूट की गई। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका रही, बल्कि उस समय की पंजाब सरकारों की भी इसमें भागीदारी थी।

मलोट हलके का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 50 सालों से ज्यादा समय से टेलों पर बैठे गांवों के लोग पानी के लिए तरस रहे थे। गांव बलमगढ़, रामगढ़, राम नगर, तरखानवाला आदि गांवों की हालत बताते हुए कहा कि यहां किसान कर्जों के नीचे दबकर दिहाड़ियां करने के लिए मजबूर हो गए। घरों में रिश्ते नहीं हुए, पिता-दादाओं की जिंदगी भी इन दुखों में कटी। उन्होंने कहा कि यह वो गांव हैं, जिन्हें कई बार मुख्यमंत्री बने अकाली और कांग्रेसी ने गोद लिया था, लेकिन हकीकत में कभी इनकी सुनवाई नहीं हुई। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि एक दिन ये बुजुर्गों को लेकर मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के पास जालंधर गईं। वहां मुख्यमंत्री ने लोगों की दर्द भरी बात सुनी और तुरंत काम शुरू करवाया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने वो हिम्मत की जो किसी सरकार ने नहीं की थी। जब पानी की बात आई, जब गांवों की आवाजें सुनने की बात आई, तो ये भगवंत मान साहब ही थे, जिन्होंने कहा कि "पहले पानी पहुंचेगा फिर चुनाव निशान।" उन्होंने कहा कि पहले लोग जीवनदायी जिएं फिर राजनीति है। उन्होंने कहा कि आज ये मलोट हलका खुशकिस्मत है कि मोघों की मरम्मत हो रही है और नहरों का पानी खेतों की टेलों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान और जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर गोयल का विशेष धन्यवाद किया।

अंत में डॉ. बलजीत कौर ने मीडिया वाहकों से विनती की कि ये केवल कहानी नहीं, आपबीती है, जो इन बुजुर्गों की जुबानी सुनी जाए। क्योंकि जो दुख-दर्द इन लोगों ने 50-50 साल सहा है, उसका जवाब भी इस सिस्टम से मांगना पड़ेगा।

उप चुनाव से पहले लुधियाना पश्चिम के लिए अंतिम वोटर सूची प्रकाशित: सिबिन सी

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किये गये शैडयूल के अनुसार, योग्यता तिथि 01.04.2025 के विशेष संक्षिप्त संशोधन के बाद ईआरओ लुधियाना पश्चिम द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार लुधियाना के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु जैन द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम वोटर सूची की कॉपियां सौंप दी गई हैं। अधिक जानकारी साझा करते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि संशोधित सूची के अनुसार लुधियाना पश्चिम क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,74,437 है, जिसमें 89,602 पुरुष मतदाता, 84,825 महिला मतदाता और 10 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं।

मतदान केंद्रों की संख्या को 192 तक तर्कसंगत बनाया गया है, जिससे मतदाताओं की पहुँच योग्यता में सुधार हुआ है और सभी नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक मतदान अनुभव को समर्थ बनाया गया है। विशेष रूप से, वोटर फोटो पहचान पत्र कवरेज को 100 प्रतिशत कर दिया गया है। सिबिन सी ने बताया कि मतदाता संशोधन सूची प्रक्रिया को संबंधित अधिनियमों और नियमों का पूर्ण पालन करते हुए, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से पूरा किया गया है। महत्वपूर्ण कदमों जैसे दावों और आपत्तियों की सूचियों को प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट और अंतिम वोटर सूचियां साझा करना आदि कार्यों की पालना पूरी गंभीरता से की गयी है। इसके अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता द्वारा ईआरओ के आदेश के विरुद्ध डीईओ को अपील करने की व्यवस्था और आवश्यकता पड़ने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) स्तर पर भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 और चुनाव रजिस्ट्रेशन नियम, 1960 के नियम 23 के उपबंध अनुसार, बैठक में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में पूरी जानकारी भी दी।

चीमा ने अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस पार्टियों को अपनी गलतियाँ स्वीकार करने और पंजाब के लोगों से माफी मांगने की चुनौती दी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से राज्य के जल मुद्दों से निपटने में ऐतिहासिक गलतियों के लिए जवाबदेही की मांग की, साथ ही उन्हें अपने कुकर्मों के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगने की चुनौती दी।

पंजाब के जल के संबंध में राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा लाए गए संकल्प पर बहस के दौरान पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के रुख ने एक महान उदाहरण स्थापित किया है, जो राज्य के हितों के प्रति उनके समर्पण को दशार्ता है। कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी

(भाजपा) सहित पिछली सरकारों की पंजाब के जल संसाधनों को बेचने में उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए आलोचना करते हुए, वित्त मंत्री ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने कार्यों के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह किया। चीमा ने कहा, "मैं आपसे इस सदन के सामने खड़े होकर पंजाब के लोगों से माफी मांगने का आग्रह करता हूं।" मंत्री चीमा ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पंजाब पर चल रहे "हमलों" की भी निंदा की, जिसमें राज्य की उधार लेने की सीमा में कमी और "काले कृषि कानूनों" का कार्यान्वयन शामिल है। चीमा ने कहा, "भाजपा के तहत केंद्र सरकार लगातार पंजाब को निशाना बना रही है।" उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, इन हमलों के खिलाफ राज्य की दृढ़ता से रक्षा करेगी।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, वित्त मंत्री चीमा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राज्य के जल मुद्दे का संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया, जिसमें पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा का एकीकृत रुख राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए राज्य के संकल्प को दशार्ता है।

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री मान को उनके साहसिक रुख के लिए धन्यवाद देकर और सदन को आश्वासन देकर अपनी बात समाप्त की कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करना जारी रखेगी। उन्होंने पंजाब के जल की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों की एकीकृत प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त की।

बी.बी.एम.बी. का गठन पिछली सरकारों की ऐतिहासिक गलती: स. हरजोत सिंह बैंस

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देशों के खिलाफ दृढ़ता से डटने के बाद, पंजाब के शिक्षा और सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा को भरोसा दिया कि वे अपने हलके श्री आनंदपुर साहिब में मौजूद भाखड़ा डैम से कभी अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ने देंगे।

पंजाब विधानसभा में संबोधन करते हुए पंजाब में पानी की गंभीर स्थिति को उजागर करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब की अर्थव्यवस्था भूजल पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कोयला, सोना या तेल के भंडार न होने के कारण, भूजल ही पंजाब का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। बता दें कि भूजल के अधिक उपयोग के कारण राज्य के 90 प्रतिशत ब्लॉक डार्क जोन घोषित किए जा चुके

हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सिंचाई नेटवर्क को 50-60 वर्षों से अनदेखा किया गया है, जिससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत खतरा है।

स. हरजोत सिंह बैंस ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे बी.बी.एम.बी एक्ट के गठन के दौरान पंजाब के हितों की रक्षा करने में असफल रही हैं, जिसके बुरे परिणामों स्वरूप राज्य के जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन और बबार्दी हुई है। श्री आनंदपुर साहिब हलके का प्रतिनिधित्व करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने अपने हलके के निवासियों, खासकर जिउवाल, बिभौर साहिब, स्वामीपुर बाग और खेड़ा जैसे गांवों, भाखड़ा मेन लाइन और नंगल डैम के निकट होने के बावजूद पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंगेर क्षेत्र के 30-35 से अधिक गांव पेयजल और सिंचाई के पानी के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान और जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल का धन्यवाद किया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में इन गांवों को पानी की आपूर्ति प्रदान की और लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित कीं।

स. हरजोत सिंह बैंस ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने नहरी पानी के उपयोग को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने किसानों को और प्रेरित करने और सिंचाई बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि हर खेत तक नहरी पानी सुनिश्चित किया जा सके जिससे भूजल के स्रोतों पर अतिरिक्त बोझ को कम किया जा सके।

गैर-कानूनी ढंग से पंजाब की जमीन पर कब्जा करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) पर बरसते हुये हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने नंगल शहर की दयनीय स्थिति का जिक्र किया, जो चंडीगढ़ के साथ ही बनाया गया था, लेकिन महज 50-60 वर्षों में ही खंडहर बन गया है। इसी प्रकार तलवाड़ा को भी अनदेखा कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नंगल में एशिया की सबसे बड़ी वर्कशॉप, जिसमें राज्य के 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकता था, बर्बाद हुई पड़ी है।

बुजुर्ग पूजन के साथ मनाया अंत्योदय उत्थान और सुशासन के प्रतीक मनोहर लाल का जन्मदिन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। साढ़े 9 साल बतौर मुख्यमंत्री सुशासन और पारदर्शिता की मिसाल पेश करने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन सेवा कार्यों के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में शहर के निर्मल धाम वृद्ध आश्रम में उनके जन्मदिन को बुजुर्ग पूजन के रूप में मनाया गया। हवन यज्ञ के साथ आयोजन की शुरूआत की गई।

स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाईस चेयरमैन सुभाष चंद्र के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, मेयर रेनू बाला गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सांसद प्रतिनिधि कविंद्र राणा ने निर्मल धाम स्थित वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों का फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद बुजुर्गों को लंगर प्रसाद खिलाया। भारत माता की जय के नारों के साथ संत निक्का सिंह स्कूल के बच्चों ने शब्द गायन कर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीन लाठर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन को सेवा कार्यों के रूप में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन पर करनाल में अनेक सेवा कार्य आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धानंद आश्रम में हवन यज्ञ के साथ गौशाला में गायों को केक खिलाया गया।

वहीं विशाल रक्तदान शिविर भी लगाया गया जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकताओं और आम लोगों ने रक्तदान कर दूसरों का जीवन बचाने का संदेश दिया। प्रवीन लाठर ने कहा कि निर्मल धाम आश्रम में हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला है। हमारे जनप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की सोच शुरू से ही अंत्योदय की रही है और उनकी इसी सोच को भाजपा भी जन सेवा के माध्यम से आगे बढ़ा रही है।

मनोहर लाल ने बिना पर्ची, बिना खर्ची की नीति को लागू करके सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। इस नीति का उद्देश्य भ्रष्टाचार, सिफारिश और रिश्वतखोरी को समाप्त कर मेधावी युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना था। इस नीति के तहत लाखों युवाओं को नौकरी मिली, बेरोजगारी दर घटी और व्यवस्था में विश्वास बढ़ा।

इस अवसर पर नगर निगम की मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का हमेशा मानना रहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे और उन्होंने लगातार इस दिशा में काम किया। मिशन मेरिट और अंत्योदय उत्थान के जरिये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। इसके जरिये न केवल गरीब वर्ग के युवाओं का नौकरी लगने का सपना पूरा हुआ बल्कि पोर्टल के जरिये उन लोगों के घर द्वार तक योजनाएं पहुंचीं, जोकि दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर थक चुके थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के बाद देश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने और हर घर जगमग करने का रोडमैप तैयार किया है।

इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन से पवन शर्मा, भाजपा नेता सुनील गुप्ता, अशोक कुरलन, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैनी, निर्मल धाम के प्रबन्धक राजेश गुप्ता, डॉ आरपी सैनी, पार्षद सुधीर यादव, सुखदेव कांगड़ा, शाहिद अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान

मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिवस पर लगाया रक्तदान शिविर

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग रेवाड़ी। सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्षा डॉ. वंदना पोपली कि अध्यक्षता में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ कोसली विधायक अनिल कुमार ने रिबन काटकर तथा रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर उनके साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामपाल यादव, परिवार पहचान पत्र के कॉर्डिनेटर सतीश खोला, पंचायतीराज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व पूर्व जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील मूसेपुर, रत्नेश बंसल व सिंहराम महलावत व डॉ अरविंद यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने हरियाणा प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देकर हरियाणा के युवाओं को उनकी प्रतिभाओ पर फिर से विश्वास दिला दिया। इसलिए उनके जन्मदिवस पर युवाओं में जोश व उत्साह है और सभी इस रक्तदान शिविर में बढ-चढ कर भाग ले रहे है।

कोसली विधायक अनिल कुमार ने रक्तदान कर रहे युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है। रक्तदाताओं के रक्तदान से न जाने कितनी जिंदगी बचाई जाती है। उन्होने कहा कि आज का आपका ये पुण्य काम किसी की जिंदगी बचाने में वरदान सिद्ध होगा।

वहीं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मनोहर लाल को जन्मदिन कि शुभकामनाएं देते हुए रक्तदान कर रहे रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए इसे पूर्व मुख्यमंत्री के सेवा भाव को समर्पित एक पुनीत कार्य बताया। उन्होंने कहा कि साढ़े नौ साल हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार निभाने के बाद, मनोहर लाल खट्टर अब केंद्र में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित है। मनोहर लाल खट्टर मजबूत नेतृत्व के धनी हैं। उन्होंने रक्तदाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि जब हम रक्तदान करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा खून किसी जरूरतमंद को नया जीवन देता है। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।

'तीन नये आपराधिक कानूनों' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आरंभ

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के डॉ एस राधाकृष्णन सम्मेलन कक्ष में 'तीन नये अपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023' विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अभियोजन विभाग हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर डॉ अरशिन्दर सिंह चावला, निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी के निर्देश पर अकादमी के जिला उप-न्यायवादी सुरेन्द्र कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न इकाइयों से प्रशिक्षण पर आए 26 लोक अभियोजक भाग ले रहे हैं। अकादमी के निदेशक कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों से रूबरू हुए तथा प्रतिभागियों ने उनके साथ समूह चित्र भी करवाया। अकादमी के जिला न्यायवादी डॉ सोहन सिंह ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक की भूमिका निभाई। लोक अभियोजन अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला उप-न्यायवादी सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि वैसे तो आप सभी कानून के ज्ञाता हैं लेकिन इस प्रशिक्षण के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप अपने अनुभवों को अपने साथियों के साझा कर सकेंगे। क्योंकि ज्ञान को जितना आपसे में बांटेंगे यह उतना ही आगे प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभिक सत्र में अतिथि वक्ता डॉ दीपा सिंह, एडवोकेट पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ ने प्रतिभगियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस अकादमी में पहले भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से प्रतिभागियों को कुछ नया सीखने का अवसर मिलता ही है साथ ही अतिथि वक्ताओं को भी कुछ नए पहलुओं के बारे जानकारी मिलती है। अकादमी का परिवेश स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है, मुझे आशा है कि स्वास्थ्य संबंधी इस अवसर का आप लाभ अवश्य उठाएंगे।

इस क्रम में उन्होंने प्रतिभागियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विषय पर कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए अकादमी के निदेशक डॉ अरशिन्दर सिंह चावला तथा अभियोजन विभाग हरियाणा का आभार व्यक्त किया।

सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ खो-खो और कबड्डी के खेले गए मैच

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। जिला खेल अधिकारी सुधा भसीन ने कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, ये न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सुधा भसीन सोमवार को स्थानीय कर्ण स्टेडियम में सांसद खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर खिलाडियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने सबसे पहले खिलाडियों का परिचय लिया और कहा कि खेल हमें स्वस्थ रहने, अनुशासित रहने और टीम भावना सीखने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से खेल हमारे हृदय और मांस-पेशियों को मजबूत बनाते हैं तथा नियमित रूप से खेलने से हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। मानसिक रूप से भी खेलों का बहुत महत्व है, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमें रणनीति बनानी होती है, त्वरित निर्णय लेने होते हैं और अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होता है। हार और जीत को स्वीकार करना खेल सिखाता है तथा खेल से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।

सुधा भसीन ने बताया कि सोमवार को सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत खो-खो और कबड्डी के मैच आयोजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के तहत खो-खो के लिए 23 टीमें आई हैं इनमें 13 पुरूषों की और 20 महिलाओं की टीमें शामिल हैं।

इसी प्रकार कबड्डी के लिए 47 टीमें आई हैं, जिनमें से 37 पुरूषों की और 10 महिलाओं की टीमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को खो-खो में 13 टीमें और कबड्डी की 19 टीमों ने मैच खेले हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता के तहत सभी खिलाडियों को स्पोर्ट्स किट दी गई है।

तार चोरी करने के मामले में सीआईए-1 पुलिस द्वारा 2 आरोपी काबू, 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल

मामले में पहले ही 2 अन्य आरोपी किए जा चुके काबू

तार चोरी करने के दोनों आरोपी सीआईए-1 पुलिस गिरफ्त में। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। तार चोरी करने के मामले में सीआईए-1 पुलिस द्वारा 2 अन्य आरोपियों को काबू कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यूएचबीवीएन एसडीओ कैथल की शिकायत अनुसार गांव नैना में 33 केवी बिजली की लाइन लगाने का काम चल रहा था, 27 अप्रैल को वहां से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 33 केवी लाइन के एसीएसआर कंडक्टर की 4500 मीटर तार चोरी कर ले गए। जिस बारे थाना पूंडरी में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच सीआईए-1 प्रभारी एसआई जसवंत की अगुवाई में एएसआई राजीव कुमार व एएसआई सुभाष की टीम द्वारा करते हुए दिल्ली से आरोपी नूरपुर जिला बिजनौर यूपी निवासी उस्मान व टोकपुर जिला बिजनौर यूपी निवासी मोमन को काबू कर लिया गया। प्रवक्ता ने बताया मामले की जांच दौरान सीआईए-1 पुलिस द्वारा पहले ही 2 आरोपियों को काबू करके वारदात में प्रयुक्त टाटा एस गाड़ी व चोरीशुदा 1025 किलोग्राम तार बरामद करके दोनो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। आरोपी उस्मान व मोमिन का व्यापक पूछताछ के लिए अदालत से सोमवार को 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया।

जिला प्रशासन की नई पहल: फीडबैक के जरिये जानेंगे जन समस्याएं

प्राथमिकता अनुसार होगा समाधान-उपायुक्त उत्तम सिंह

एसबी विशेष संवाददाता करनाल। शहरवासियों की समस्याओं को जानने और उनका समाधान करने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल की है। इसके तहत घर-घर कूड़ा एकत्र करने वाले वाहनों के जरिये लोगों तक फीडबैक फॉर्म पहुंचाया जाएगा। इस फार्म में 5 व्यक्तिगत और 5 वार्ड अथवा शहर को प्रभावित करने वाली समस्याएं दर्ज करनी होंगी। दो दिन बाद फार्म वापस लेकर समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता अनुसार उनका समाधान किया जाएगा।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक नागरिक प्रतिक्रिया फार्म तैयार किया है। इसे कूड़ा एकत्र करने वाले वाहनों के जरिये घर-घर तक पहुंचाया जाएगा और इन्हीं के माध्यम से दो दिन बाद इस फार्म को वापस लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस फार्म में व्यक्तिगत और सामूहिक पांच-पांच उन समस्याओं का उल्लेख किया जाए जिनका संबंध नगर निगम, जिला प्रशासन अथवा सरकार से है। मसलन फीडबैक फार्म में शहर में यातायात की समस्या दर्ज करने की बजाय कहां से कहां (क्षेत्र का नाम) तक ट्रैफिक समस्या है, इसका उल्लेख करें। साथ ही समस्या के समाधान के लिए संभव हो तो सुझाव भी लिखें।

उन्होंने बताया कि घर के सामने गली अथवा सडक पर बना गड्ढा, मेनहोल का खुला ढक्कन, पीपीपी, प्रापर्टी आईडी आदि से संबंधित व्यक्तिगत समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं जबकि वार्ड अथवा शहर को प्रभावित करने वाली पांच समस्याओं को फार्म के क्रमांक नंबर तीन में दर्ज करना होगा। उपायुक्त के अनुसार फीडबैक फार्म में समस्याओं को हिंदी अथवा अंग्रेजी में दर्ज किया जा सकता है। यदि कोई पंजाबी अथवा अन्य किसी भाषा में समस्या का उल्लेख करना चाहे तो कर सकता है।

उम्मीद जताई कि 70-80 हजार फार्म फीडबैक के बाद वापस प्रशासन के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाएगा और प्राथमिकता अनुसार उनका समाधान भी। उन्होंने बताया कि फीडबैक फार्म वापस मिलने के बाद जिला प्रशासन को पता चल जाएगा कि सडकों की क्वालिटी, पेयजल संकट, यातायात समस्या, कूड़ा-एकत्र करने, घर के आगे से गुजर रही बिजली की तारों आदि के बारे में कितनी शिकायतें आई हैं। यदि किसी वार्ड अथवा कालोनी में सार्वजनिक पार्क नहीं है तो उसके बारे में भी लोग प्रतिक्रिया फार्म में लिख सकते हैं। दिनचर्या में कौन सी चीज लोगों के लिए बेहतर हो सकती है, इस बारे सुझाव दिया जा सकता है।

राजकीय प्राथमिक पाठशाला बीर बांगडा में दीपक शर्मा ने पांच पंखे किया दान

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। खंड राजौंद के राजकीय प्राथमिक पाठशाला बीर बांगडा में दीपक शर्मा उर्फ कालू शर्मा ने अपनी नेक कमाई में से पांच पंखे दान कर एक अनूठी व अनूकरणीय मिसाल पेश कर नेक काम किया है। जानकारी देते हुए विद्यालय के शिक्षक राजकुमार राजौंद ने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला बीर-बांगडा में हालांकि इससे पहले समय समय पर कई दानी सज्जनों ने पाठशाला में स्टेशनरी, वर्दी, जर्सी, पंखे के साथ साथ प्रीति भोज का प्रबंध किया है।

लेकिन गांव के निवासी होने के नाते दीपक उर्फ कालू शर्मा ने अनुकरणीय व अद्वितीय पहल जरूरतमंद की है। इस के लिए दीपक शर्मा बधाई एवं प्रशंसा के पात्र है। इस अवसर पर दानी सज्जन दीपक उर्फ कालू शर्मा ने अपने संबोधन में भविष्य में भी यथासंभव एव यथाशक्ति प्राथमिक पाठशाला में सभी प्रकार से सहयोग व मदद करने का आश्वासन दिया है। विद्यालय स्टाफ ने उनके इस नेक व अनुकरणीय कार्य के लिए धन्यवाद किया। साथ ही विद्यार्थियों ने भी दीपक उर्फ कालू शर्मा के मंगल भविष्य तथा घर परिवार, व्यापार, आजीविका में दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की व सफलता की हार्दिक शुभकामनायें दी है। इस अवसर पर विद्यालय प्रभारी रामनिवास, शिक्षक राजकुमार, शिक्षक आनंद कुमार, शिक्षक जोगिंदर सिंह के साथ साथ सुभाष शर्मा तथा दौलत शर्मा सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

साइबर अपराधों से बचने के लिए रहें सजग व सतर्क: उपायुक्त उत्तम सिंह

साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर दर्ज करवाएं शिकायत

एसबी विशेष संवाददाता करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि बढ़ते हुए साइबर अटैक अथवा साइबर अपराधों को रोकने में सरकार, प्रशासन ही नहीं उपभोक्ता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे हमलों को रोकने में उपभोक्ताओं की सजगता और सतर्कता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। साइबर अटैक के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता, फोरम, वेबसाइट पर अपनी संवेदनशील जानकारी ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर न करें। अपना पासवर्ड मजबूत रखें, कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले देखें कि वह वेबसाइट ठीक है या नहीं। उन्होंने कहा कि सिस्टम की सुरक्षा के लिए अपने सिस्टम को अपडेट करते रहें और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें।

उन्होंने बताया कि स्पैम मैसेज को खोलने से बचें और ओपन वाईफाई का इस्तेमाल न करें। साथ ही एक ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करें। आप एक सुरक्षित नेटवर्क से जुडकर सावधानी और सजगता बरतकर साइबर हमले अथवा अपराध की गिरफ्त में आने से बच सकते हैं।

इसी कड़ी में पुलिस विभाग द्वारा भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1930 शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अटैकर्स कमजोर सिस्टम पर हमला करने और उस पर नियंत्रण करने के लिए मैलिसस कोड का सहारा लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर अटैक अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं। इसके लिए मैलवेयर, फिशिंग अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, मेन इन द मिडिल के माध्यम से किया जा सकता है। इसको सिस्टम को हैक करने, क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसे की मांग के लिए या फिर डार्क वेब पर डेटा बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस तरह के हमले में संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जानकारी जो उपयोगकर्ता की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसे बिना किसी वेबसाइट या यूजर्स के ज्ञान के हाईजैक किया जा सकता है।

साईबर सिक्योरिटी टिप्स: उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि यदि आप इंटरनेट का उपयोग बैंकिंग से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं, तो आपको अपने डिवाइस में साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एंटी वायरस को जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। एक अच्छा एंटी वायरस आपको मैलवेयर और डाटा सिक्योरिटी बीच के खतरे से बचाने का काम करता है।

दयालु योजना है देश में अपनी तरह की अनूठी योजना

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हर गरीब परिवार को सामाजिक व आर्थिक रूप से उन्नत बनाने की सोच है। इसके लिए मुख्यमंत्री न सिर्फ निरंतर जन कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर भी पूरा कर रहे हैं। यही नहीं मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वयं डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से 2286 लाभार्थियों के खाते में 86.93 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उल्लेखनीय है कि अंत्योदय परिवारों में परिवार के कमाने वाले मुखिया की दुर्घटना में मौत हो जाने पर उन्हें ढांढस बंधाने व परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत अब तक 28644 लाभार्थियों को एनपीसीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 1076.275 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही भेजी जा चुकी है।

देश में अपनी तरह की हरियाणा की इस अनूठी योजना के तहत 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक के व्यक्ति की दुर्घटना में या अकाल मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 6 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे की मृत्यु होने पर परिवार को 1 लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष की आयु तक के किशोर की मौत होने पर 2 लाख रुपये, 18 से 25 आयु तक के युवक की मौत होने पर 3 लाख रुपये, 25 से 50 आयु तक के (जो आमतौर पर परिवार का मुखिया होता है और कमाने वाला होता है) व्यक्ति की मौत होने पर 5 लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे मामले में जहां लाभार्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष तक है तथा परिवार में कोई नाबालिग लड़की है तो 5 लाख रुपये की सहायता राशि में से 2.5 लाख रुपये नाबालिग लड़की के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।

गौरतलब होगा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने ऐसे गरीब परिवारों के प्रति अति संवेदनशील हैं और हमेशा सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

घर में आग लगने से भारी नुक्सान, सरकार प्रशासन से मदद की गुहार

एसबी ब्यूरो राजौंद। राजौंद के वार्ड चार, आगडी पट्टी में अज्ञात कारणों से घर में आग लगने से भारी नुक्सान होने की सूचना मिली है। पुष्पा देवी धर्मपत्नी स्व. तेजपाल ने पुलिस थाना राजौंद में लिखित दरखास्त में लिखा है कि पांच मई दोपहर एक बजे उसके घर में आग लगने से भारी नुक्सान हो गया है। आग लगने के समय वह पडौस के घर में किसी काम से गयी हुई थी। बेटा व बहू काम धंधे पर गए हुए थे। पोते पोतियां स्कूल गये थे। उसे मकान से धुआं निकलने की सूचना मिली। उसने आकर के देखा तो उसके घर का सारा सामान जल चुका था। बताया गया कि घर में काफी महंगे सूट फर्नीचर था। जो सब चल कर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई व पुलिस थाना राजौंद में सूचना दी गई है। बताया गया कि लगभग एक लाख का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने सरकार व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद की पत्नी को आवासीय प्लाट देने को मंजूरी दी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिला फरीदाबाद के गांव अटाली निवासी शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने के ग्राम पंचायत अटाली (जिला फरीदाबाद) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नायक संदीप ने 19 फरवरी, 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। परिवार की परिस्थितियों और पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी को देखते हुए, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विचार किया गया और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई। प्लाट का आवंटन पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के नियम 13ए के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। हरियाणा सरकार राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।